गोम्रा

+

*1175. { श्री युद्धवीर सिंह :
श्री ग्रोंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री मधु लिमये :
श्री रामसेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री कोया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री कनकसबै :
श्री नाथ पाई :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गोम्रा को महाराष्ट्र में मिलाने के सम्बन्ध में ग्रन्तिम निर्णय कर लिया है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री युद्धवीर सिंह : यह प्रश्न प्राय: प्रत्येक सत्र में उठता है ग्रौर इसके बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि गोम्रा के भविष्य के बारे में निर्णय लेने में सरकार के मार्ग में कौन से सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक, सांस्कृतिक, ग्राधिदैविक, ग्राधिभौतिक कारण या रोड़े हैं कि सरकार गोम्रा के बारे में ग्रन्तिम निर्णय लेने में इतनी देरी कर रही है ?

श्री हाथी : ग्राधिभौतिक, नैतिक, राजनितक, सामाजिक, सभी बातें हैं जरूर । ये बातें इसलिए हैं कि जो ग्रलग ग्रलग प्रांत हैं उनसे बात करनी होगी, वहां के जो लोग हैं उनसे बात करनी होगी । सभी प्रकार की बातें करके फिर सोच विचार कर निर्णय करना होगा ।

श्री युद्धवीर सिंह : लोगों से बात करने की बात सरकार ने कही । पिछले दिनों महाराष्ट्र की ग्रसेम्बली में एक मत से यह प्रस्ताव पास किया था कि गोम्रा को महाराष्ट्र में मिलाया जाए । मैं समझता हूं कि एक मत का ग्रर्थ माननीय मंत्री समझते होंगे । ग्रौर इसी प्रकार गोम्रा की विधान सभा ने भी इस बारे में प्रस्ताव पास किया, वह बहुमत से पास हुग्रा था, एक मत से नहीं । गोम्रा के जो चुनाव हुए उनसे भी यह बात स्पष्ट हो गयी कि जनता यह चाहती है कि गोम्रा को महाराष्ट्र के साथ मिला दिया जाए. . .

ग्रध्यक्ष महोदय : यहां बहस तो नहीं हो सकती ।

श्री युद्धवीर सिंह : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि गोम्रा के बारे में जो ये दोनों प्रस्ताव पास किए गए उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ग्रौर उस प्रतिक्रिया के प्रकाश में वह क्या निर्णय लेने जा रही है ?

ग्रध्यक्ष महोदय : जवाब दिया जा चुका है ।

श्री युद्धवीर सिंह : प्रस्तावों की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

ग्रध्यक्ष महोदय : प्रस्तावों के बारे में भी ग्रा चुका है ।

Shri Hathi: It is true that a Resolution had been passed by the Maharashtra Assembly. It is also true that the Goa Assembly has passed a Resolution and we have taken note of both these Resolutions. So far as Goa is concerned, it was not unanimous.

श्री युद्धवीर सिंह : मैं प्रतिक्रिया के बारे में पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि वह अभी सोच रहे हैं ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती : माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ बातें हैं जिनके ऊपर विचार करेंगे । पिछली बार गोआ में 54 हजार लड़के मराठी की प्राथमिक परीक्षा में बैठे और कन्नड़ भाषा की परीक्षा में केवल एक हजार लड़के बैठे । क्या इस कारण इसको महाराष्ट्र में मिलाया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप तो बहस करते हैं । इस वक्त बहस नहीं हो सकती ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या गोआ को महाराष्ट्र में न मिलाने का यह कारण है कि पिछले चुनावों में हमारी सरकार हार गयी ? पहले यह वायदा किया था कि इसको मिलाया जाएगा, अब न मिलाने का क्या कारण है ?

श्री हाथी : यह कारण नहीं है । अभी सारी बातें विचाराधीन हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : माननीय मंत्री जी ने बताया कि मामला विचाराधीन है । गोआ का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में और कुछ हिस्सा मैसूर में मिलाने के बारे में अन्तिम निर्णय लेने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : यह सवाल नहीं उठता कि कितना हिस्सा दिया जाएगा । इसके बारे में कहा जा चुका है कि विचार हो रहा है और जहां तक हो सकेगा जल्द फैसला किया जाएगा । समय नहीं दिया जा सकता ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : समय के बारे में कुछ नहीं बताया कि समय कितना लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि कहा नहीं जा सकता है अब मैं इससे ज्यादा क्या पूछ सकता हूं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : समय की बाबत नहीं बतलाया ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप ही बतलाइये मैं क्या करूं ?

श्री मधु लिमये : गोवा, दीव, दमन और पांडेचेरी आदि इलाकों को बगल के प्रांतों में मिलाने का प्रश्न, तथा अन्तरप्रान्तीय सीमा विभागों के प्रश्न को हल करने के लिए सरकार के पास कोई जनतांत्रिक सिद्धांत है ? अगर ऐसा सिद्धांत है तो उस पर अमल करने से देशहित होगा । अगर हर सवाल को हल करने के लिए खून खराबी, प्रान्तीयता का जहर फैलाने और आपस में मारपीट करने का ही रास्ता सरकार ने जनता को दिखाया तो उसके राष्ट्र के लिए बड़े खतरनाक नतीजे निकलगे । इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई प्रजातांत्रिक सिद्धांत इन मसलों को हल करने का है ? जब एक दफा ऐसा सिद्धांत बन जाता है तो सभी मसले उसके आधार पर हल कर सकते हैं । तो गोवा के सम्बन्ध में क्या कोई ऐसा सिद्धांत है .....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । He wants to know whether there are any principles on which these things are to be decided.

श्री नन्दा : जब कुछ फैसला होगा तो वह किसी सिद्धांत के आधार पर ही होगा ।

श्री मधु लिमये : मैंने कौन सिद्धांत है यह पूछा था ।

श्री नन्दा : मैं और नहीं बतला सकता ।

श्री मधु लिमये : कोई जनतांत्रिक सिद्धांत है ? लोगों के संतोष से क्या मतलब कोई जनतांत्रिक तरीका तो होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : वह और न बतलाना चाहें तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री मधु लिमये : आप उन्हें कहिये ।

श्री किशन पटनायक : गोवा मिश्रण के बारे में कोई नीति तय न करने का क्या यह राजनीतिक कारण है ? सरकार दो मुंही बात करना चाहती है । रेल तथा रक्षा मंत्री एक तरफ़ के लोगों का समर्थन करना चाहते हैं और दूसरे लोग दूसरी तरफ़ समर्थन करना चाहते है और गोवा को अपना बनाये रखना चाहते हैं क्या यह बात सही नहीं है ?

श्री नन्दा : यह बिल्कुल सही नहीं है । इसमें मतभेद नहीं है ।

Shri Koya: May I know whether the question of Goa is being considered indepently or along with other liberated foreign possessions in India like Pondicherry and Mahe?

Shri Nanda: At the moment, we are considering only this question of Goa.

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार को मालूम है कि गोवा मर्जर और ऐंटी मर्जर आन्दोलन जोरशोर से चल रहा है तो क्या सरकार का इरादा है कि गोवा की सब पार्टियों को इधर बुला कर राउंड टेबल कांफ्रेंस की जाय ?

श्री नन्दा : अभी राउंड टेबल कांफ्रेंस करने का कोई इरादा नहीं है ।

श्री शिव नारायण : क्या गोवा के विलय के बारे में मैसूर विधान सभा ने कोई खास विचार प्रकट किये हैं ? और सरकार के पास भेजे हैं ?

श्री नन्दा : मैसूर के भी अपने व्यूज हैं जिनको कि उन्होंने प्रकट किया है ।

श्री तुलशीदास जाधव : गोवा के महाराष्ट्र में मर्ज करने के बारे में 10वर्षों से जो ऐलान किया जाता रहा है क्या सरकार उस पर अभी भी कायम है या उस पर फिर से सरकार विचार करने वाली है ?

श्री नन्दा : हम आगे भी कह चुके हैं कि इस सारे मामले पर फिर से विचार चल रहा है ।

श्री मधु लिमये : सिद्धांत हीन विचार और सिद्धांत हीन सरकार ।

Shri H. K. Veeranna Gowda: As ragards the resolution p ased by the Goa Assembly suggesting the merger of Goa with Maharashtra, may I know by how many number of votes it was passed by them?

Mr. Speaker: That he can know from the records.

Shri Alvares: The Government has not been able to identify yet what are the special considerations for keeping Goa as a Union Territory. At the same time, since Goa's liberation, certain agents of foreign Governments have been attempting a sabotage with a view to encouraging certain sections of India not to accept the fact of liberation of Goa. In view of the national security of the country, may I know whether the Government will effect the merger soon and give a lie to their expectations?

Mr. Speaker: That is a suggestion.

Shri Shinkre: It is said, on behalf of the Government, that ten years time should be given because the people of Goa are not yet ripe for democracy. In this connection. I want to know from the Home Minister. . .

Mr. Speaker: Today at least this has not been said.

Shri Shinkre: It has been said before. In this context, I want to know from the hon. Home Minister whether for this Government the concept of democracy means majority for the Congress Party and, secondly, whether the Government will wait to take a decision on the merger of Goa until Maharashtra and Mysore

States go in a proper warfare and, thirdly, whether the Government will wait . . .

Mr. Speaker: Prof. Hem Barua is getting many pupils.

Shri Shinkre:....until such time the situation in Goa boils sufficiently to something similar to that of Naga hostilesso that they will be compelled to take some action. I would like the Home Minister to reply to all these three questions of mine.

Mr. Speaker: I would allow him to answer only one if he can.

Shri Nanda: The one answer which I would like to give about democracy and all that is that all the assumptions, the strings and series of assumptions, are baseless.

Shri Shinkre: What about the other two questions?

Shrimati Renu Chakravartty: In view of the fact that the question of the merger of Goa is agitating the minds of a large part of the country, could we be assured that the Government is going to take a decision within a very short time and, if so, what will be the time-limit?

Shri Nanda: So far as the time-limit is concerned, I have said that I would not be in a position to state the time-limit. But I have also said very clearly that we would like to take a decision very early and this matter is being considered.

Shri Basappa: In view of the Emergency which exists in the country, will the Government postpone the question of the merger of Goa for the time being—and also as per the assurance given by the late Prime Minister, the difference of opinion that exists in Goa and outside Goa, and also in view of the resolution passed by the Mysore Assembly, and because of other historical, administrative and other things?

Mr. Speaker: It is a suggestion. Next Question.

Shri Nath Pai rose—

Mr. Speaker: He has just now come.

Shri Nath Pai: I was here before you had gone to the next Question.

Mr. Speaker: No; Shri Indrajit Gupta ..absent Shrimati Maimoona Sultan.

Exodus of Minorities from East Pakistan

+

*1177. { **Shrimati Maimoona Sultan:** **Shri Sidheshwar Prasad:** }

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Commission of Inquiry set up to investigate into the causes of exodus of minorities from East Pakistan has requested Government to arrange for an on-the-spot study of the matters involved in East Pakistan;

(b) if so, whether Pakistan Government have been approached to seek their permission for the purpose; and

(c) if so, the response from Government of Pakistan thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

12.00 hrs.

SHORT NOTICE QUESTION

Haldia Refinery

S.N. 13. Dr. L. M. Singhvi: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that most of the international oil companies have lost interest in the Haldia refinery project owing to India's refusal to enter into long term agreement with any of them for the supply of crude oil for the refinery;